यूपी ने पेश किया भारत का पहला 'ग्रीन बजट'

कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नई पहल, प्रदेश के 17 विभागों को ग्रीन टैगिंग देने की हुई शुरुआत

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने भारत का पहला ग्रीन बजट सोमवार को पेश किया। बजट में पर्यावरण फ्रेंडली आर्थिक रणनीति का ताना-बुना बुना गया है। बजट में पर्यावरण के अनुकूल नीतियां, ग्रीन गैसों के उत्सर्जन को कम करने वाला माहौल तैयार करने, प्राकृतिक संसाधन की रक्षा आदि पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने ग्रीन बजट की अवधारणा को सार्थक करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। प्रदेश के 17 विभागों को ग्रीन टैगिंग देने

की शुरुआत की है। ग्रीन टैगिंग करने के मामले में यूपी पहला राज्य होगा।

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है, दुनिया के सभी देशों ने वर्ष 2030 तक तापमान में वृद्धि रोकने का लक्ष्य तय किया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत ने भी संकल्प लिया है। इसे देखते हुए यूपी ने अपने बजट में पर्यावरण को लेकर खासा काम किया है। मालूम रहे कि ग्लास्गो में हुए 26 वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'पंचामृत' कार्यों को लेकर वचनबद्धता जाहिर की थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन मुक्त ऊर्जा को बढ़ाना, नवीनीकरण स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन गैसों की तीव्रता को कम करना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूपी कई कदम उठा रहा है और जमीन पर इससे जुड़ी नीतियों को लागू कर रहा है। इसके लिए राज्य सौर ऊर्जा नीति, राज्य जैव ऊर्जा नीति और राज्य इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति पर तेज काम करने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए राजकोषीय रणनीति में ग्रीन बजटिंग को पेश किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 24-25 में ग्रीन बजट टैगिंग की शुरुआत करके वित्तीय योजनाओं को पर्यावरण के साथ जोड़ने का कदम उठाया है। ग्रीन बजटिंग के तहत ग्रीन एनर्जी कारीडोर भी बनाने का प्रस्ताव है।